भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–07 फरवरी, 2019

बघेल भी रमण के नक्शेकदम
आत्मरक्षा में प्रतिरोध करने जनता का आह्वान!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सुकमा जिले के पोलंपल्ली फर्जी मुठभेड़ जिसमें एक आदिवासी महिला की निर्मम हत्या की गयी एवं एक अन्य महिला को घायल किया गया था, की घोर निंदा करती है. हमारी पार्टी जनता का आह्वान करती है कि वह अपनी आत्मरक्षा में हरसंभव तरीके से प्रतिरोध करे.

लोकलुभावन वादों व नारों, आदिवासियों के दमन की पिछली सरकार की नीतियों की खिलाफत करते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस अपनी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के ही नक्शेकदम जन दमनकारी नीतियों पर खुलकर अमल कर रही है. भूपेश बघेल के शपथ ग्रहण के समय से ही गांवों में गश्त, माओवादियों, माओवादी समर्थकों, मिलिशिया के नाम पर ग्रामीणों की गिरफ्तारियां, हमारे कार्यकर्ताओं पर फायरिंग बेरोकटोक जारी हैं. कांकेर के माटियाखार से लेकर छत्तीसगढ़–महाराष्ट्र सरहदी भावे, मूसपरसी, सुकमा जिले के डब्बाकुंटा, तुलसी डोंगरी तक लगातार हम पर हमलें हो रहे हैं. अब सुकमा के पोलंपल्ली के आस–पास ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को निशाना बनाकर नजदीक से गोली मारकर यह झूठी घोषणा की गयी कि मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गयी और एक को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है. जनता के जबर्दस्त विरोध एवं जनता, जनवादी, मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उक्त सफेद झूठ का पर्दाफाश हो गया तब नक्सलियों के साथ क्रास फायरिंग में मारे जाने की एक और झूठी कहानी गढ़ी गयी. उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की यह घोषणा कि जांच करवाकर पीड़ित को मुआवजा दिलाया जाएगा, झूठी मुठभेड़ में मृत व घायल महिलाओं के प्रति ही नहीं बल्कि समूची आदिवासी जनता के साथ ही क्रूर मजाक है. इससे लखमा ने यह साबित किया कि आदिवासी नेता होने के बावजूद वह भी शोषक–शासक वर्गों के ही सेवक हैं और उनके ही हितपूर्ति करने वाले हैं.

हमारी पार्टी छत्तीसगढ सहित देश भर के आदिवासी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़े तबकों की जनता, जनवादी–प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, जनपक्षधर मीडियाकर्मियों, आदिवासी व गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार व महिला संगठनों का आह्वान करती है कि वे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की जन दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें एवं पोलंपल्ली झूठी मुठभेड़ की स्वतंत्र न्यायिक जांच करवाकर पुलिस, अर्ध–सैनिक व डीआरजी, एसटीएफ बलों के दोषी अधिकारियों व जवानों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करें.

विकल्प

(विकल्प)
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)